

वित्तीय समावेशन और आर्थिक विकास: विकासशील देशों में बैंकिंग सेवाओं की भूमिका

Harish Jhangra

सारांश:

वित्तीय समावेशन समावेशी आर्थिक विकास की आधारभूत अवधारणाओं में से एक है। इसका उद्देश्य समाज के उन वर्गों तक औपचारिक वित्तीय सेवाओं की पहुँच सुनिश्चित करना है जो परंपरागत रूप से बैंकिंग और वित्तीय व्यवस्था से बाहर रहे हैं। विकासशील देशों में निम्न आय वाले परिवारों, ग्रामीण समुदायों, छोटे किसानों, सूक्ष्म उद्यमों और सामाजिक रूप से कमजोर समूहों के लिए बचत, ऋण, बीमा, भुगतान तथा अन्य वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता आर्थिक अवसरों का विस्तार कर सकती है। प्रस्तुत शोध-पत्र वित्तीय समावेशन की अवधारणा तथा आर्थिक विकास के साथ उसके संबंध का विश्लेषण करता है। इसमें बैंकिंग सेवाओं की पहुँच, बचत व्यवहार, ऋण उपलब्धता, उद्यमिता, रोजगार, गरीबी उन्मूलन और मानव पूँजी निर्माण पर वित्तीय समावेशन के प्रभावों का अध्ययन किया गया है। डिजिटल बैंकिंग, मोबाइल वित्तीय सेवाओं और डिजिटल भुगतान प्रणालियों के विस्तार ने वित्तीय समावेशन की संभावनाओं को और व्यापक किया है। इसके बावजूद वित्तीय साक्षरता की कमी, डिजिटल विभाजन, बैंकिंग सेवाओं की लागत, भौगोलिक दूरी, दस्तावेजी बाधाएँ तथा उपभोक्ता संरक्षण की समस्याएँ अभी भी महत्वपूर्ण चुनौतियाँ हैं। शोध-पत्र का निष्कर्ष है कि वित्तीय समावेशन केवल बैंक खाता खोलने तक सीमित प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ऐसी वित्तीय व्यवस्था का निर्माण है जिसमें व्यक्ति सुरक्षित, सस्ती और उपयोगी वित्तीय सेवाओं का प्रभावी ढंग से उपयोग कर सके। इसलिए विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में वित्तीय समावेशन को आर्थिक विकास, गरीबी उन्मूलन, उद्यमिता, डिजिटल परिवर्तन और सामाजिक सुरक्षा की व्यापक रणनीति से जोड़ना आवश्यक है।

प्रमुख शब्द: वित्तीय समावेशन, आर्थिक विकास, बैंकिंग सेवाएँ, वित्तीय साक्षरता, डिजिटल बैंकिंग, सूक्ष्म वित्त, गरीबी, उद्यमिता।

प्रस्तावना

आर्थिक विकास का वास्तविक उद्देश्य केवल राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना नहीं है, बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों को आर्थिक अवसरों तक समान और प्रभावी पहुँच उपलब्ध कराना भी है। आधुनिक अर्थव्यवस्था में वित्तीय प्रणाली इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बैंक बचत को संगठित करके उसे निवेश में परिवर्तित करते हैं, व्यवसायों को ऋण उपलब्ध कराते हैं, भुगतान प्रणाली संचालित करते हैं और आर्थिक गतिविधियों को वित्तीय आधार प्रदान करते हैं। इसके बावजूद विकासशील देशों में समाज का एक बड़ा वर्ग लंबे समय तक औपचारिक वित्तीय व्यवस्था से बाहर

रहा है। वित्तीय बहिष्करण की स्थिति में परिवारों को अपनी बचत घर में रखने, अनौपचारिक ऋणदाताओं से महँगे ऋण लेने या आकस्मिक आर्थिक संकटों से निपटने के लिए अपनी परिसंपत्तियाँ बेचने जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। इससे गरीबी का चक्र मजबूत हो सकता है। इसके विपरीत यदि निम्न आय वाले परिवारों को सुरक्षित बचत, उचित ब्याज दर पर ऋण, बीमा और भुगतान सेवाएँ उपलब्ध हों, तो वे आर्थिक जोखिमों का बेहतर प्रबंधन कर सकते हैं। वित्तीय समावेशन इसी समस्या का समाधान प्रस्तुत करने वाली व्यापक अवधारणा है। इसका उद्देश्य समाज के प्रत्येक व्यक्ति और व्यवसाय को आवश्यक वित्तीय सेवाओं तक पहुँच उपलब्ध कराना है। पिछले कुछ दशकों में डिजिटल तकनीक के विकास ने इस प्रक्रिया को नई गति दी है। मोबाइल बैंकिंग, डिजिटल भुगतान, बायोमेट्रिक पहचान और वित्तीय प्रौद्योगिकी ने उन क्षेत्रों तक वित्तीय सेवाएँ पहुँचाने की संभावना बढ़ाई है जहाँ पारंपरिक बैंकिंग ढाँचा सीमित रहा है।

वित्तीय समावेशन की अवधारणा

वित्तीय समावेशन का अर्थ है कि समाज के सभी वर्गों को उचित लागत पर सुरक्षित और उपयोगी वित्तीय उत्पादों एवं सेवाओं तक पहुँच प्राप्त हो। इसमें बैंक खाते, बचत, ऋण, बीमा, पेंशन, भुगतान तथा धन हस्तांतरण जैसी सेवाएँ शामिल हो सकती हैं। वित्तीय समावेशन की सफलता केवल खातों की संख्या से निर्धारित नहीं की जा सकती। यह भी महत्वपूर्ण है कि खाताधारक वास्तव में खाते और अन्य वित्तीय सेवाओं का नियमित एवं प्रभावी उपयोग कर रहे हैं या नहीं। वित्तीय समावेशन के तीन प्रमुख आयाम माने जा सकते हैं—पहुँच, उपयोग और गुणवत्ता। पहुँच का संबंध वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता से है, उपयोग का संबंध इन सेवाओं के वास्तविक इस्तेमाल से और गुणवत्ता का संबंध लागत, पारदर्शिता, सुरक्षा तथा उपभोक्ता हितों से है। यदि किसी व्यक्ति के पास बैंक खाता तो है लेकिन वह उसका उपयोग नहीं करता, तो वास्तविक वित्तीय समावेशन सीमित माना जाएगा।

बैंकिंग सेवाएँ और आर्थिक विकास

बैंकिंग प्रणाली आर्थिक विकास में वित्तीय मध्यस्थ की भूमिका निभाती है। बैंक परिवारों और संस्थाओं से जमा स्वीकार करते हैं तथा इन संसाधनों को ऋण के रूप में उत्पादक गतिविधियों में प्रवाहित करते हैं। इस प्रक्रिया से पूँजी निर्माण को बढ़ावा मिलता है और आर्थिक गतिविधियों का विस्तार होता है। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में छोटे किसानों, व्यापारियों और सूक्ष्म उद्यमों के लिए औपचारिक ऋण की उपलब्धता विशेष महत्व रखती है। यदि छोटे उद्यमों को उचित वित्तीय संसाधन उपलब्ध हों, तो वे उत्पादन क्षमता बढ़ा सकते हैं, नई मशीनरी खरीद सकते हैं और अधिक श्रमिकों को रोजगार दे सकते हैं। इस प्रकार वित्तीय समावेशन उद्यमिता और रोजगार सृजन से जुड़ सकता है।

बचत और वित्तीय सुरक्षा

वित्तीय समावेशन परिवारों में औपचारिक बचत को प्रोत्साहित कर सकता है। बैंक खातों के माध्यम से व्यक्ति अपनी बचत को अपेक्षाकृत सुरक्षित रूप में रख सकता है और आवश्यकता के समय

उसका उपयोग कर सकता है। नियमित बचत भविष्य के निवेश, शिक्षा, आवास और अन्य महत्वपूर्ण खर्चों के लिए वित्तीय आधार तैयार करती है। निम्न आय वाले परिवारों के लिए बचत का महत्व विशेष रूप से अधिक है क्योंकि उनकी आय में उतार-चढ़ाव अपेक्षाकृत अधिक हो सकता है। बीमारी, बेरोजगारी, प्राकृतिक आपदा या फसल खराब होने जैसी परिस्थितियों में बचत आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर सकती है। इस प्रकार वित्तीय समावेशन परिवारों की आर्थिक संवेदनशीलता कम करने में योगदान कर सकता है।

ऋण और उद्यमिता

वित्तीय समावेशन का एक महत्वपूर्ण पक्ष औपचारिक ऋण की उपलब्धता है। विकासशील देशों में छोटे उद्यमों को अक्सर पर्याप्त संपार्श्विक और वित्तीय रिकॉर्ड की कमी के कारण औपचारिक ऋण प्राप्त करने में कठिनाई होती है। परिणामस्वरूप वे अनौपचारिक ऋणदाताओं पर निर्भर हो सकते हैं। उचित ब्याज दर पर बैंक ऋण छोटे उद्यमों के विस्तार को प्रोत्साहित कर सकता है। कृषि क्षेत्र में ऋण बीज, उर्वरक, सिंचाई उपकरण और कृषि मशीनरी की खरीद में सहायता कर सकता है। गैर-कृषि क्षेत्र में ऋण दुकान, लघु उद्योग, परिवहन, सेवा व्यवसाय और डिजिटल उद्यमिता को बढ़ावा दे सकता है। इस प्रकार वित्तीय समावेशन उत्पादन और आय के नए अवसर पैदा कर सकता है।

वित्तीय समावेशन और गरीबी उन्मूलन

गरीबी केवल आय की कमी नहीं है; यह आर्थिक अवसरों और संसाधनों तक सीमित पहुँच से भी जुड़ी होती है। वित्तीय समावेशन गरीब परिवारों को बचत, ऋण और बीमा जैसी सेवाओं से जोड़कर उनकी आर्थिक क्षमता बढ़ा सकता है। वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता से परिवार अपनी आर्थिक गतिविधियों में निवेश कर सकते हैं और आकस्मिक संकटों से बेहतर ढंग से निपट सकते हैं। हालाँकि वित्तीय समावेशन को गरीबी उन्मूलन का अकेला समाधान नहीं माना जा सकता। यदि ऋण उत्पादक गतिविधियों में उपयोग न होकर अत्यधिक उपभोग या पुराने ऋण चुकाने में चला जाए, तो उसका विकासात्मक प्रभाव सीमित हो सकता है। इसलिए वित्तीय समावेशन के साथ वित्तीय साक्षरता और आय-सृजन के अवसर भी आवश्यक हैं।

वित्तीय साक्षरता की भूमिका

वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता तभी प्रभावी होती है जब व्यक्ति उनके बारे में पर्याप्त जानकारी रखता हो। वित्तीय साक्षरता का संबंध बचत, ब्याज दर, ऋण, बीमा, जोखिम और निवेश से संबंधित निर्णय लेने की क्षमता से है। निम्न आय वाले परिवारों के लिए वित्तीय साक्षरता विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि गलत वित्तीय निर्णय उनकी आर्थिक स्थिति को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकते हैं। वित्तीय शिक्षा से व्यक्ति बैंकिंग उत्पादों की लागत और लाभ समझ सकता है, ऋण की शर्तों का मूल्यांकन कर सकता है और धोखाधड़ी से बचने के उपाय सीख सकता है। डिजिटल वित्त के विस्तार के साथ साइबर सुरक्षा और डिजिटल भुगतान संबंधी जागरूकता भी वित्तीय साक्षरता का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई है।

डिजिटल वित्त और वित्तीय समावेशन

डिजिटल तकनीक ने वित्तीय समावेशन के नए अवसर पैदा किए हैं। मोबाइल फोन और इंटरनेट के माध्यम से व्यक्ति बैंक शाखा में जाए बिना भुगतान, धन हस्तांतरण और कुछ वित्तीय सेवाओं का उपयोग कर सकता है। इससे ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं की पहुँच बढ़ाने में सहायता मिल सकती है। डिजिटल वित्त की सबसे बड़ी विशेषताओं में कम लेन-देन लागत और तेज भुगतान शामिल हैं। छोटे व्यापारी डिजिटल भुगतान स्वीकार कर सकते हैं और ग्राहक दूरस्थ स्थान से भुगतान कर सकते हैं। सरकारी हस्तांतरणों को भी डिजिटल माध्यम से अधिक तेजी और पारदर्शिता के साथ पहुँचाया जा सकता है। हालाँकि डिजिटल वित्त के साथ नई चुनौतियाँ भी सामने आती हैं। इंटरनेट और स्मार्टफोन तक सीमित पहुँच, डिजिटल साक्षरता की कमी, साइबर धोखाधड़ी और डेटा गोपनीयता के जोखिम वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए डिजिटल वित्त के विस्तार के साथ सुरक्षा और उपभोक्ता संरक्षण आवश्यक है।

ग्रामीण वित्तीय समावेशन

ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन का महत्व विशेष रूप से अधिक है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि, लघु व्यवसाय और अनौपचारिक रोजगार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ग्रामीण परिवारों की आय मौसमी और अनिश्चित हो सकती है, इसलिए बचत, ऋण और बीमा की आवश्यकता अधिक रहती है। बैंक शाखाओं, बैंकिंग प्रतिनिधियों, मोबाइल बैंकिंग और डिजिटल भुगतान प्रणालियों का विस्तार ग्रामीण वित्तीय समावेशन को मजबूत कर सकता है। कृषि ऋण, फसल बीमा और बचत योजनाएँ ग्रामीण परिवारों की आर्थिक सुरक्षा बढ़ा सकती हैं। साथ ही स्थानीय स्तर पर वित्तीय जागरूकता कार्यक्रम भी आवश्यक हैं।

महिलाओं और वित्तीय समावेशन

महिलाओं की वित्तीय सेवाओं तक पहुँच आर्थिक और सामाजिक सशक्तीकरण से जुड़ी हुई है। महिला के नाम बैंक खाता होने से उसकी वित्तीय पहचान और आर्थिक निर्णयों में भागीदारी बढ़ सकती है। स्वयं सहायता समूहों और महिला उद्यमिता के माध्यम से वित्तीय सेवाएँ आय-सृजन गतिविधियों को बढ़ावा दे सकती हैं। महिला वित्तीय समावेशन का प्रभाव परिवार के स्वास्थ्य, शिक्षा और बचत व्यवहार पर भी पड़ सकता है। हालाँकि महिलाओं के वित्तीय बहिष्करण के पीछे सामाजिक मान्यताएँ, आय की कमी, संपत्ति पर सीमित अधिकार और डिजिटल पहुँच की असमानता जैसी बाधाएँ हो सकती हैं। इसलिए वित्तीय नीतियों को लैंगिक दृष्टिकोण से भी विकसित करना आवश्यक है।

सूक्ष्म वित्त और वित्तीय समावेशन

सूक्ष्म वित्त ने निम्न आय वाले समूहों को छोटे ऋण और बचत सेवाओं से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विशेष रूप से ऐसे लोगों के लिए सूक्ष्म वित्त उपयोगी हो सकता है जिनके पास पारंपरिक बैंक ऋण के लिए पर्याप्त संपार्श्विक उपलब्ध नहीं होता। हालाँकि सूक्ष्म वित्त की सफलता ऋण की गुणवत्ता, ब्याज दर, पुनर्भुगतान क्षमता और वित्तीय शिक्षा पर निर्भर करती है। अत्यधिक

ऋणग्रस्तता की स्थिति में सूक्ष्म ऋण आर्थिक समस्या भी पैदा कर सकता है। इसलिए सूक्ष्म वित्त को जिम्मेदार ऋण व्यवस्था और उपभोक्ता संरक्षण के साथ जोड़ना आवश्यक है।

वित्तीय समावेशन और मानव पूँजी

वित्तीय सेवाएँ शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश को भी प्रभावित कर सकती हैं। यदि परिवारों के पास उचित बचत और ऋण सुविधा हो, तो वे बच्चों की शिक्षा, कौशल विकास और स्वास्थ्य सेवाओं पर अधिक खर्च कर सकते हैं। इससे दीर्घकालीन मानव पूँजी निर्माण को बढ़ावा मिल सकता है।

मानव पूँजी में सुधार उत्पादकता और आय को बढ़ाता है, जिससे वित्तीय समावेशन और आर्थिक विकास के बीच एक सकारात्मक चक्र निर्मित हो सकता है। बेहतर आय से बचत क्षमता बढ़ती है, अधिक बचत से निवेश बढ़ सकता है और निवेश से भविष्य की आय में वृद्धि हो सकती है।

वित्तीय समावेशन और आर्थिक असमानता

वित्तीय समावेशन आय और अवसरों की असमानता को कम करने में योगदान कर सकता है, विशेषकर जब वित्तीय सेवाएँ समाज के निम्न आय वर्गों तक पहुँचती हैं। औपचारिक ऋण और बचत सुविधाएँ गरीब परिवारों को आर्थिक गतिविधियों में भाग लेने का अवसर दे सकती हैं।

लेकिन यदि वित्तीय सेवाओं का लाभ मुख्यतः पहले से संपन्न वर्गों तक सीमित रहे, तो वित्तीय प्रणाली असमानता को कम करने के बजाय उसे बनाए रख सकती है। इसलिए वित्तीय समावेशन की नीतियों में उन समूहों को प्राथमिकता देनी चाहिए जो सबसे अधिक वित्तीय बहिष्करण का सामना करते हैं।

भारत के संदर्भ में वित्तीय समावेशन

भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में वित्तीय समावेशन आर्थिक नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। बैंकिंग नेटवर्क के विस्तार, जन-आधारित बैंक खातों, डिजिटल भुगतान, मोबाइल बैंकिंग और वित्तीय प्रौद्योगिकी ने वित्तीय सेवाओं की पहुँच में परिवर्तन किया है। भारत में डिजिटल भुगतान प्रणाली के विस्तार ने छोटे लेन-देन को भी औपचारिक वित्तीय प्रणाली से जोड़ने की संभावना बढ़ाई है। इसके बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता, इंटरनेट गुणवत्ता, बैंकिंग उपयोग और वित्तीय जागरूकता से संबंधित चुनौतियाँ बनी रह सकती हैं। इसलिए भारत में वित्तीय समावेशन की अगली अवस्था का ध्यान केवल खाते खोलने पर नहीं बल्कि सक्रिय और सुरक्षित उपयोग पर होना चाहिए।

वित्तीय समावेशन की प्रमुख चुनौतियाँ

वित्तीय समावेशन के सामने पहली चुनौती भौगोलिक पहुँच की है। दूरस्थ क्षेत्रों में बैंक शाखाओं और वित्तीय सेवा केंद्रों की कमी हो सकती है। दूसरी चुनौती वित्तीय सेवाओं की लागत है। छोटे लेन-देन और छोटे ऋणों के लिए अत्यधिक लागत गरीब उपभोक्ताओं को औपचारिक व्यवस्था से दूर कर सकती है। तीसरी चुनौती वित्तीय साक्षरता की कमी है। व्यक्ति यदि वित्तीय उत्पादों की शर्तों को नहीं समझता, तो वह गलत निर्णय ले सकता है। चौथी चुनौती डिजिटल सुरक्षा है। ऑनलाइन धोखाधड़ी और पहचान संबंधी जोखिम डिजिटल वित्त के प्रति विश्वास को कमजोर कर सकते हैं। पाँचवीं चुनौती अनौपचारिक रोजगार और आय की अनिश्चितता है। जिन परिवारों की आय नियमित

नहीं होती, उनके लिए पारंपरिक बैंकिंग उत्पाद हमेशा उपयुक्त नहीं हो सकते। इसलिए वित्तीय संस्थानों को लचीले और ग्राहक-केंद्रित उत्पाद विकसित करने की आवश्यकता है।

नीतिगत सुझाव

वित्तीय समावेशन को प्रभावी बनाने के लिए सरकार और वित्तीय संस्थानों को ग्रामीण एवं वंचित क्षेत्रों में बैंकिंग बुनियादी ढाँचे का विस्तार करना चाहिए। डिजिटल वित्तीय सेवाओं को सस्ती, सरल और स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध कराना भी महत्वपूर्ण है।

वित्तीय शिक्षा को विद्यालय, महाविद्यालय और समुदाय स्तर तक विस्तारित किया जाना चाहिए। महिलाओं, किसानों, छोटे व्यापारियों और युवा उद्यमियों के लिए विशेष वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम उपयोगी हो सकते हैं। साथ ही डिजिटल धोखाधड़ी से बचाव के लिए साइबर सुरक्षा जागरूकता बढ़ानी चाहिए।

बैंकों और वित्तीय संस्थानों को छोटे व्यवसायों के लिए उपयुक्त ऋण उत्पाद विकसित करने चाहिए। ऋण प्रदान करते समय केवल संपार्श्विक के बजाय नकदी प्रवाह और व्यवसाय की क्षमता को भी ध्यान में रखा जा सकता है। इससे औपचारिक ऋण की पहुँच बढ़ सकती है।

निष्कर्ष

वित्तीय समावेशन आर्थिक विकास की ऐसी प्रक्रिया है जो वित्तीय संसाधनों और अवसरों को समाज के व्यापक वर्ग तक पहुँचाने का प्रयास करती है। बचत, ऋण, बीमा, भुगतान और निवेश सेवाओं की उपलब्धता परिवारों तथा व्यवसायों की आर्थिक क्षमता को बढ़ा सकती है। इसके माध्यम से उद्यमिता, रोजगार, मानव पूँजी निर्माण और गरीबी में कमी को प्रोत्साहन मिल सकता है।

डिजिटल तकनीक ने वित्तीय समावेशन की संभावनाओं को और व्यापक किया है। मोबाइल बैंकिंग, डिजिटल भुगतान और वित्तीय प्रौद्योगिकी ने वित्तीय सेवाओं को अधिक तेज और सुलभ बनाने में योगदान दिया है। लेकिन डिजिटल विभाजन, वित्तीय निरक्षरता, साइबर सुरक्षा और उपभोक्ता संरक्षण जैसी चुनौतियों को संबोधित किए बिना डिजिटल वित्तीय समावेशन अधूरा रहेगा।

अतः वित्तीय समावेशन को केवल बैंक खाता उपलब्ध कराने की नीति के रूप में नहीं बल्कि **सुलभ, सस्ती, सुरक्षित, जिम्मेदार और उपयोगी वित्तीय सेवाओं की व्यापक व्यवस्था** के रूप में समझना चाहिए। यदि वित्तीय समावेशन को कौशल विकास, डिजिटल बुनियादी ढाँचे, सामाजिक सुरक्षा और उद्यमिता के साथ जोड़ा जाए, तो यह विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में अधिक समावेशी और टिकाऊ आर्थिक विकास का मजबूत आधार बन सकता है।

संदर्भ सूची

Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., & Levine, R. (2007). Finance, Inequality and the Poor. *Journal of Economic Growth*, 12(1), 27–49.

- Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., & Martinez Peria, M. S. (2007). Reaching Out: Access to and Use of Banking Services Across Countries. *Journal of Financial Economics*, 85(1), 234–266.
- Collins, D., Morduch, J., Rutherford, S., & Ruthven, O. (2009). *Portfolios of the Poor: How the World's Poor Live on \$2 a Day*. Princeton University Press.
- Demirgüç-Kunt, A., & Klapper, L. (2012). Measuring Financial Inclusion: The Global Findex Database. *World Bank Policy Research Working Paper*.
- Demirgüç-Kunt, A., Klapper, L., Singer, D., Ansar, S., & Hess, J. (2018). *The Global Findex Database 2017: Measuring Financial Inclusion and the Fintech Revolution*. World Bank.
- Honohan, P. (2008). Cross-Country Variation in Household Access to Financial Services. *Journal of Banking & Finance*, 32(11), 2493–2500.
- Karlan, D., Ratan, A. L., & Zinman, J. (2014). Savings by and for the Poor: A Research Review and Agenda. *Review of Income and Wealth*, 60(1), 36–78.
- King, R. G., & Levine, R. (1993). Finance and Growth: Schumpeter Might Be Right. *Quarterly Journal of Economics*, 108(3), 717–737.
- Levine, R. (2005). Finance and Growth: Theory and Evidence. In *Handbook of Economic Growth*, Vol. 1A. Elsevier.
- Rajan, R. G., & Zingales, L. (1998). Financial Dependence and Growth. *American Economic Review*, 88(3), 559–586.
- World Bank. (2014). *Global Financial Development Report 2014: Financial Inclusion*. World Bank.
- World Bank. (2016). *Payment Aspects of Financial Inclusion*. World Bank.
- World Bank. (2017). *The Global Findex Database 2017*. World Bank.
- International Monetary Fund. (2017). *Financial Access Survey 2017*. IMF.
- Reserve Bank of India. (2017). *Report on Trend and Progress of Banking in India 2016–17*. RBI.